करना पड़ा। इसका स्थानीय जनता ने काफी विरोध भी किया किन्तु सरकार द्वारा उनकी मांग अनसुनी कर दी गई। 75 से 80 किलोमीटर की परिधि में प्रसारण करने वाला यह केन्द्र मात्र 20-25 किलोमीटर दूर पूर्णिया में अपनी क्षमता प्रमाणित करने में असफल हो रहा है। लगातार बारिश या वातावरण में अधिक नमी होने के कारण एल०एन०बी०सी० में नमी आ जाती है जिससे कई बार चित्र एवम् ध्वनि स्पष्ट दिखाई व सुनाई नहीं पड़ता है। कटिहार पूर्वोत्तर बिहार के कई जिलों के केन्द्र में अवस्थित है, इसलिए यहां न्यूज़ रिकार्डिंग तथा प्रोग्राम जेनेरेटिंग फेसेलिटी दी जाए तथा एक कैमरामैन की भी नियुक्ति की जाए जिससे स्थानीय कार्यक्रम को भी दिखाया जा सके।

अंत मे मैं आग्रह करूंगा कि कटिहार दूरदर्शन केन्द्र में अविलम्ब नई मशीन लगाई जाए जिससे आम जनता के द्वारा दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सही रूप से देखा व सुना जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Closure of Textile Mills in Ahmcdabad, Gujarat.

श्री अहमद पटेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विशेष उल्लेख के जरिए मैं अहमदाबाद स्थित टैक्सटाइल मिल वर्कर्स की दयनीय और चिंताजनक स्थिति की ओर केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, पिछले कई दिनों से अहमदाबाद में जो टैक्सटाइल मिल वर्कर्स है, अपने रोजगार के लिए, अपने सरवाइवल के लिए आन्दोलन कर रहे है और उनकी जो मांगे हैं, जायज़ मांगें हैं। वह इस बात का प्रमाण है कि वहां की सारी यूनियनें - "इंटक", "सीटू", "जीएसटी-सी", "एनटीसी" और "पीएलए" — उनका समर्थन कर रही हैं। मान्यवर, पिछले कुछ सालों में निजी क्षेत्र की, जीएसटीसी की और एनटीसी की या तो कुछ मिलें बंद हो गई है या कुछ बंद होने की तैयारी में हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि जो हजारों टैक्सटाइल मिल वर्कर्स हैं या जो उनके परिवार हैं, उनकी स्थिति आज बड़ी दयनीय और चिंताजनक है और इससे हजारों वर्कर्स और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। आज उन परिवारों की स्थिति, मैं समझता हूं कि बहुत ही चिंताजनक है। ये परिवार, मैं समझता हूं, खास तौर पर जो टैक्सटाइल मिल वर्कर्स हैं, जो अपनी रोजी-रोटी या अपनी आमदनी इन मिलों के जरिए चलाते थे, आज यहां तक हो गया है कि बेकार होने की वजह से कई परिवारों ने अपने बर्तन बेच दिए हैं, उनकी महिलाओं ने अपने जेवर बेच दिए हैं और आमदनी न होने की वजह से उनके बच्चे शिक्षा नहीं ले पर रहे हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो भुखमरी की स्थिति में जी रहे हैं। मान्यवर, अगर इंसान बेकार होता है तो अच्छी तरह से आप जानते है कि वह क्या-क्या करने के लिए सोचता है। आज वहां पर एक सामाजिक तनाव पैदा हुआ है। मान्यवर, आज उन वर्कर्स की मांग यह है कि अगर एनटीसी वाले अपनी मिलें गुजरात में चला सकते हैं और अपने 20,000 वर्कर्स को रोजी-रोटी और काम दे सकते है तो जीएसटीसी की, गुजरात सरकार की जो मिलें हैं, उन्हें गुजरात सरकार क्यों नहीं चला सकती? वहां की प्रदेश सरकार का रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बीआईएफआर ने उन मिलों के बारे में प्रदेश सरकार को कहा कि वह कोई योजना या स्कीम बनाकर उनके सम्मुख रखें, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई स्कीम या योजना बीआईएफआर के सामने नहीं रखी, बल्कि मुझे लगा कि उनका रवैया जीएसटीसी की जो मिलें हैं, उनको बंद करने के बारे में है। पूर्व की जो सरकारें थीं, उसका रवैया हमेशा वर्कर्स के हक में रहा और जैसा कि सब जानते हैं, पूर्व सरकारों ने एनआरएफ को एक योजना बनाकर दी थी, एक मसौदा बनाकर दिया था और जिसमें यह कहा गया था कि 168 करोड़ रुपए की धनराशि इन मिल वर्कर्स की सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाए। लेकिन वह स्कीम, वह योजना भी मैं समझता हूं कि आज कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है।

तो वहां की स्थिति गंभीर है और वहां के वर्कर्स की हालत चिंताजनक है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि टेक्सटाइल मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, फाईनेंस मिनिस्टर वहां की सरकार के प्रतिनिधियों और मजदूर यूनियंस के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाकर जल्द से जल्द इस बारे में ऐसा हल ढूंढा जाए कि इन परिवारों को बरबादी से बचाया जा सके।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): महोदय, मैं इस स्पेशल मैंशन के साथ ऐसोसिएट करता हूं। इस बारे में एक कॉलिंग अटैंशन भी आने वाला था, कल आ रहा है लेकिन दुःख की बात है कि सरकार इस बारे में कोई ऐक्शन नहीं ले रही है...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): टैक्सटाईल मजदूरों की समस्या के बारे में कल चर्चा होगी।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बारे में तुरंत कार्यवाही करे और हमारे साथी

पटेल जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Sir, I...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Your name will be there for association.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: I have given separate notice for a Short Duration discussion which is still pending.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI MD. SALIM): It will come in any form but you cannot convert the Special Mentions into a Short Duration Discussion.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, 72 thousand workers were thrown out on the street and they are jobless and the closure of 22 mills is imminent throwing 20,000 more workers on the street. Therefore, all the unions of all the political parties including the BJP 1" ve formed a *manch.* They have come on the road. The *Rasta Roko Andolan* is going on and the Government is not doing anything. It will not only be a social problem but even a law and order problem in Ahmedabad. Therefore, I have suggested to my friend, Shri lalappa, the Textile Minister to visit Ahmedabad and try to find a way out to see that these workers do not *go* on committing suicide. Stamp-Duty Scam in U.P. SHRI GOVINDRAM MIRI (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman Sir, through you, I would like to draw the attention of the Government of India as well as the Governor of U.P. to the stamp-duty scam services in U.P. Sir, the U.P. Government has been deprived of the stamp duty to the tune of Rs. 35.59 crores in the case of transfer of properties of Indian Explosives Limited, a fertiliser manufacturing unit of the I.C.I. India Limited to Chand Chhaap Fertiliser and Chemicals Limited, promoted by Duncan Industries Limited of R.P. Gocnka Group in connivance with the obliging Deputy Registrar, Stamps and Revenues, Kanpur. Sir, in January 1995 an enquiry was-instituted wherein Mr. R.R. Gupta, the then Deputy Registrar (Registration) and the then Additional District Magistrate (Finance), Kanpur were found responsible for the financial losses to the State Government. Instead of taking punitive action against the erring officer, the State Government preferred to 'reward' Mr. Gupta by posting him at a better posting. It is not the only scam to surface in the sprawling State of U.P. During the last six months about 150 inquiries into scams were entrusted to the economic offences wing of the State Police. Most of the charges in these scams are levelled against IAS, IPS officers, engineers and personnel from treasury and education department. Sir, in March this year, the Economic Offences Wing registered a case of forgery against Dr. Shivraj Singh, Director in the Ay-urved Directorate. He is accused of bungling Rs. 47 crore in buying medicines and drugs. Even the amount was withdrawn without approval of the budget. So, Sir, looking into all this I would like to urge upon the Government to set up a scam excavation office or department in the State of U.P.

Need to Increase the Central Funds for Indira Gandhi Canal Project of Rajasthan

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और संयोग से संबंधित मंत्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर वे गंभीरता से विचार करें। मैं राजस्थान नहर — इंदिरा गांधी नहर योजना के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1958 से यह नहर योजना प्रारम्भ हुई। अब दो वर्ष में 40 साल इसको पूरे हो जाएंगे। इसकी लागत इस आधार पर कितनी बढ़ चुकी है इसके आंकड़े मुझे अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। 37.38 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होनी है और इसलिए इसका महत्व, इसकी उपदेयता अपने आप में स्वयं सिद्ध है। फंड की कमी के कारण ही यह मामला इतना लम्बा होता जा रहा है। केवल राजस्थान इसका खर्चा वहन नहीं कर सकता। इसीलिए भारत सरकार ने बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको सहायता दी है। आठवीं योजना में 860 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, जो इसको मदद मिलेगी और अगर यह मिल जाती तो सन्